



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 1997/पौष 27, 1918

No. 10]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 1997/PAUSA 27, 1918

बाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 394 (पी एन)/92—97

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997

फा. सं. 1/7/126/96-97/पी. सी.-2 :—यथासंशोधित, निर्यात और आयात नीति, 1992—97 के पैरा 16 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-1) 1992-97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1996) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. (i) शुल्क छूट योजना के अधीन अध्याय 7 में पैरा 123 (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़ा जायेगा, नामतः :
- 123(iii) विशिष्ट मामलों में, जहाँ शुल्क मुक्त लाइसेंसधारक प्रमाणिक और वास्तविक आधार पर निर्यात दायित्व के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में इसी अनुपात में बृद्धि करने में असमर्थ रहता है तो अग्रिम लाइसेंसिंग समिति माशा आधारित अग्रिम लाइसेंस के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य में बृद्धि करने के लिए ऐसे आवेदनों पर विचार कर सकती है बशर्ते ऐसी बृद्धि के बाद मूल्य संवर्धन नीति के पैरा 60 में दिए गए निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से कम न हो और यह इस शर्त के भी अधीन है कि नियिष्ट उत्पादन मानदण्डों में और नीति में कोई परिवर्तन न किया गया हो जिसके अनुसार लाइसेंस जारी किया गया था।
2. शुल्क छूट योजना के अधीन अध्याय 7 में पैरा 124 और 125 को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जायेगा :—
 - (क) पैराग्राफ 124 में, उक्त पैरा के अंतिम वाक्य को हटा दिया जाएगा और इस पैरा के अन्त में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जाएगा, नामतः—

“निर्यात दायित्व की अवधि समाप्त होने के दो महीने बाद निर्यात दायित्व की अवधि में बृद्धि संबंधी किसी भी अनुरोध को सामान्यतः संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी या विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय द्वारा नामंजूर कर दिया जाएगा। तथापि, विशिष्ट मामलों में निर्यात दायित्व की अवधि समाप्त होने की तारीख से दो महीने के बाद निर्यात दायित्व की अवधि में बृद्धि के लिए प्राप्त अनुरोध पर अग्रिम लाइसेंसिंग समिति, द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है, जहाँ आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए लाइसेंसधारक द्वारा पर्याप्त कारण दिए गए हैं।”
 - (ख) पैराग्राफ 125 में, उक्त पैरा के अंतिम वाक्य को हटा दिया जाएगा और उक्त पैरा के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा, नामतः—

“लाइसेंस की वैधता अवधि की समाप्ति की तारीख के दो महीने बाद पुनः वैधीकरण के लिए किसी आवेदन (आवेदनों) को सामान्यतः, जैसा विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुख्यालय अथवा संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी, जैसा मामला हो, द्वारा रद्द किया जा सकता है तथापि, विशेष मामलों में, जहाँ लाइसेंसधारक द्वारा दी गई सूचना में आवेदन को देरी से प्रस्तुत करने के

पर्याप्त आधार विद्यमान होंगे, लाइसेंस की वैधता अधिक की समाप्ति की तारीख के दो महीने बाद प्राप्त हुए पुनः वैधीकरण के आवेदन (आवेदनों) पर गुण-दोष के आधार पर अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। ”

3. इसे सोकहित में जारी किया जाता है।

एस. बी. महापात्र, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE NO. 394 (PN)/92—97
New Delhi, the 17th January, 1997

F. No. 1/7/126/96-97/PC. II :—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992-97, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Hand Book of Procedures (Vol. 1), 1992-97 (Revised Edition : March, 1996).

2. I. In Chapter VII, under Duty Exemption Scheme, after paragraph 123 (ii) thereof, the following new sub-paragraph shall be added namely :

123 (iii) In exceptional cases, where a duty free licence holder is unable to give the enhancement in fob value of export obligation in the same proportion, on bona-fide and genuine grounds, the ALC may consider such requests for enhancement in the cif value of a quantity based advance licence, provided that the value addition after such enhancement does not fall below the stipulated minimum value addition laid down in para 60 of the Policy, and also provided that there is no change in the input-output norms, and the Policy in accordance with which the licence was issued.

- JI. In Chapter VII under Duty Exemption Scheme, the paragraph 124 and 125 shall be amended in the manner indicated below :—

- (a) In paragraph 124 thereof, the last sentence of the said paragraph shall be deleted and the following sentence shall be added at the end of the said paragraph, namely :—

"Any request (s) for extension in export obligation period made beyond two months after the expiry of export obligation period would ordinarily be liable to be rejected by the concerned Regional Licensing Authority or Hqrs. office of DGFT as the case may be. However, in special cases, request (s) received for extension in export obligation period after the expiry of two months from the date of expiry of export obligation period can be considered, on merits, by ALC, where sufficient grounds for delay in submission of application is found to exist on furnishing of information by the licence holder."

- (b) In paragraph 125 thereof, the last sentence of the said paragraph shall be deleted and the following sentence shall be added at the end of the said paragraph, namely :—

"Any request (s) for revalidation made beyond two months after the date of expiry of validity period of the licence would ordinarily be liable to be rejected by the concerned regional Licensing authority or Hqrs. Office of DGFT as the case may be. However, in special cases request (s) received for revalidation after the expiry of two months from the date of expiry of validity period of the licence can be considered, on merits, by ALC, where sufficient grounds for delay in submission of application is found to exist on furnishing of information by the licence holder."

3. This issues in public interest.

S. B. MAHAPATRA, Director General of Foreign Trade.